

प्रतिलिपि

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि० की कान्फ्रेंस कॉल

तारीख / समय : 22 मई 2012

अवधि : 56 मिनट 58 सैकिण्ड

प्रस्तुतीकरण सत्र :

संचालक : सभी महिलाओं और महानुभावों को नमस्कार! मैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि० के प्रबंधन की ओर से आप सभी निवेशकों और ब्रोकरों का स्वागत करता हूँ। इस सम्मेलन का आयोजन 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा करने के लिए किया गया है। अब मैं आपको मंच पर बैठे पीएफसी प्रबंधन दल के बारे में परिचय कराऊंगा। मंच पर बीच में श्री सतनाम सिंह जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बैठे हुए हैं। उनकी दायीं ओर श्री एम के गोयल, निदेशक – वाणिज्यिक हैं। श्री सतनाम सिंह जी के बायीं ओर श्री के. एम. साहनी – स्वतंत्र निदेशक बैठे हुए हैं। उनके बायीं ओर प्रो० आर एच ढोलकिया – स्वतंत्र निदेशक हैं और उनकी बायीं ओर श्री पी मुरली मोहन राव – स्वतंत्र निदेशक हैं। इनकी बायीं ओर श्री एस सी गुप्ता स्वतंत्र निदेशक हैं। अब मैं श्री सतनाम सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे निवेशकों और ब्रोकरों को परिणामों के बारे में जानकारी दें।

सतनाम सिंह : सभी को नमस्कार। तिमाही के तथा वर्ष के आंकड़ों के बारे में बताने से पहले आपको यह बताना आवश्यक है कि भारतीय विद्युत क्षेत्र में क्या हो रहा है और इस बारे में हम किस प्रकार से विचार करते हैं। भारतीय विद्युत क्षेत्र में प्रथम और प्रमुख बात क्षमता में अत्यधिक बढ़ोत्तरी होने की हुई है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी यह जानते हैं कि 11वीं योजना के दौरान क्षमता में बढ़ोत्तरी 10वीं योजना की बढ़ोत्तरी से ढाई गुना अधिक थी। प्रसन्नता की बात यह है कि विद्युत क्षेत्र बेहतर किस्म चीजों के लिए 50 प्रतिशत प्राप्तकर्ता के अपने प्रतिरूप में बदलाव ला सका है। यदि आप पिछले 15 वर्षों के आंकड़ों को देखते हैं, तो सरकार ने 5 वर्षों के प्रत्येक वर्ष के लिए जो भी योजना बनायी थी, वास्तविक उपलब्धि केवल उसके लगभग 50 प्रतिशत के बीच में थी। अर्थात् किस प्रकार से भारतीय विद्युत क्षेत्र को 50 प्रतिशत प्राप्तकर्ता के रूप में वर्गीकृत कराया गया था। यह कहते हुए कि अत्यधिक क्षमता अभिवृद्धि विद्युत आपूर्ति जैसे कुछ मुद्दे सामने आए हैं और लोगों ने अत्यधिक क्षमता के बारे में बातें करना आरंभ कर दिया है और इसलिए क्या डिस्काम अपनी वित्तीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उतनी विद्युत खरीद सकेगा। अतः इन मुद्दों पर हम किस प्रकार से विचार करते हैं?

स्वयं मेरा और हमारी कम्पनी का मत यह है कि व्यापक क्षमता अभिवृद्धि यह संकेत दे रही है अथवा यह दर्शा रही है कि अगले 25 वर्षों में कोयले की खपत उससे भी अधिक होने जा रही है। क्षमता में जो भी अभिवृद्धि की गई है, यह कम से कम 25 वर्षों के लिए ही है। अतः उतनी ही कोयले की खपत होने जा रही

है और इस क्षेत्र के द्वारा अन्य कंपनियों के लिए यह एक आश्वासन है । इसलिए, यह कोयला और रेलवे की उत्पादन क्षमता, अथवा परिवहन (ढुलाई) क्षमता जो भी मामला हो, को बढ़ाने के लिए उन्हें अवसर दे रहा है । इसके अलावा, ईंधन आपूर्ति करने के मुद्दे को उच्चतम स्तर, प्रधानमंत्री के कार्यालय के स्तर पर उठाया गया है, जिसके बाद कोल इंडिया से मूल रूप से वचनबद्ध कोयले के आपूर्ति के 80 प्रतिशत बराबर आपूर्ति करने के करार पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुरोध किया गया है। अब कुछ लोगों का यह मत है कि कोल इण्डिया जिस 0.01 प्रतिशत दंड का प्रस्ताव कर रहा है, वह दंड राशि उस राशि की तुलना में कम है, जिस राशि का डेवलपर ने बल्क उपभोक्ता को भुगतान करना है । अब एक व्यक्ति ऐसा कह सकता है, परंतु मेरा सुझाव है कि जो कुछ भी पहले हो रहा था, इसे उसके परिवर्तन के रूप में देखना चाहिए । क्या पहले भी आपने कभी यह सुना था कि सार्वजनिक क्षेत्र की एक कम्पनी निष्पादन न करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी कंपनी को क्षतिपूर्ति करने का वचन देती है, चाहे यह एमटीएनएल थी, यदि वे आपको टेलीफोन समय पर उपलब्ध नहीं कराते हैं अथवा उस मामले के लिए गेल भी थी, यदि वे गैस की आपूर्ति न कर सकी हो अथवा डीडिए थी, यदि वे आपको नियत तारीख पर मकान उपलब्ध नहीं कराती थी । अन्य पार्टी के लिए क्षतिपूर्ति करने की कोई प्रणाली (सिस्टम) अथवा संरचना नहीं थी । अतः कोल इण्डिया की प्रस्तावित दंड की शर्त उस दिशा में एक कदम है । इस तरीके से इसे देखना चाहिए बजाए लाभ की मात्रा के, जो यह देगी । इसके अलावा कोयले के आवंटन में बुनियादी तौर पर पारदर्शिता लाने और मुद्दों का शीघ्रता से समाधान करने की दृष्टि से, जो भविष्य में आ सकते हैं, सरकार एक कोल रेगुलटर की स्थापना करने पर विचार कर रही है ।

भारतीय विद्युत क्षेत्र में एक अन्य रुझान देखने में आ रहा है वह है निचली क्षेत्र की भागीदारी । दसवीं योजना में यह 9 प्रतिशत थी । मुझे विश्वास है कि आपको इन आंकड़ों के बारे में जानकारी है लेकिन इनको सही परिप्रेक्ष्य में लागू करने के लिए इनकी संख्या के बारे में मेरा उल्लेख करना वाजिब (उपयुक्त) है । 11वीं योजना में यह 42 प्रतिशत थी और 12वीं योजना में इसके 55 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच होने की उम्मीद है । उधारदाताओं, निवेशकों और यहां तक कि उपभोक्ताओं के लिए इसका आशय क्या है, वह यह है कि इसका अभिप्राय अधिक दक्षता एवं विद्युत का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण से होता है । इसके अलावा, भारत सरकार ने दो बड़े कदम उठाए थे, एक था अत्यधिक बड़ी विद्युत परियोजनाएं और दूसरा स्वतंत्र पारेषण परियोजनाएं जिनको प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर स्थापित किया जाना था। प्रारम्भिक नौ की तुलना में 15 यूएमपीपी की पहचान कर ली गई है और अब तक 4 परियोजनाओं के बारे में निर्णय कर लिया गया है। अन्य परियोजनाएं संशोधित दिशा-निर्देशों तथा दस्तावेजों की कमी के कारण प्रक्रियाधीन है जिन पर मंत्रालय और हम साथ-साथ कार्य कर रहे हैं तथा उनके शीघ्र ही सामने आने की उम्मीद है । इसी प्रकार, 12 स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के बारे में अब तक पहचान कर ली गई है, 8 परियोजनाओं के बारे में निर्णय कर लिया गया है, 4 के बारे में हमारे द्वारा तथा 4 के बारे में आरईसी के द्वारा निर्णय लिया गया है । हमारे पास इस समय एक परियोजना जारी है और 3 परियोजनाओं को संगत उत्पादन केंद्रों को चालू करने के लिए रखा गया है । यूएमपीपी पहलों और आईटीपी पहलों दोनों से यह पता चला है कि भविष्य में टैरिफ दरें कम होने जा रही हैं और परियोजनाओं का निर्माण करने में कम समय लगेगा तथा बेहतर दक्षता पैरामीटरों को भी लागू किया जाएगा । पारेषण प्रभारों को 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक कम किया गया है जिनके लिए एक विशेष

आधार हेतु निर्णय करने के लिए सीईआरसी के एमओयू आधारित अथवा लागत आधारित संरचना का प्रयोग किया जाता था ।

डिस्काम्स की वित्तीय स्थिति चिंता का दूसरा बड़ा विषय है। हमने देखा है कि पहले की तुलना में अधिकाधिक राज्य टैरिफ में संशोधन करने जा रहे हैं। वस्तुतः अपील के इस निर्णय के बाद सकारात्मक प्रभाव हो रहा है कि विनियामक आवश्यक परिवर्तन सहित टैरिफ में संशोधन कर सकते हैं, चाहे डिस्काम्स ने विनियामक के पास वार्षिक राजस्व वसूली याचिका दायर न की हो। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में 15 राज्यों की तुलना में वर्ष 2012-13 के लिए 23 राज्यों ने पहले ही टैरिफ याचिका दायर कर दी है जिसका अभिप्राय यह है कि अधिक राज्यों के द्वारा टैरिफ में संशोधन किया जा रहा है जिससे डिस्काम्स के राजस्व प्रवाह में अंततः सुधार आएगा । पुनः निर्मित एपीडीआरपी स्कीम, जिसकी हम नोडल एजेंसी है, इसके माध्यम से घाटे को कम करने का काफी बड़े पैमाने पर प्रयास किया जा रहा है और यह कार्य तेजी से चल रहा है । अब तक 194 कस्बों को एकीकृत किया गया है जिसका अभिप्राय यह है कि ये 194 कस्बे एक स्थान पर आनलाइन सभी उपभोक्ताओं के बारे में आंकड़े प्राप्त कर रहे हैं । 1200 अतिरिक्त कस्बों में रिग फैंसिंग का कार्य किया गया है, 469 कस्बों के लिए बेसलाइन डाटा स्थापित किए गए हैं। उन्नयन प्रणाली के पहले से ही परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है अर्थात् पुनः निर्मित एपीडीआरपी स्कीम के भाग ख के तहत कुछ राज्यों ने घाटे में कमी लाने के लिए सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपना कर तथा प्रशासनिक उपाय करके पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है । आपकी सूचना के लिए कि उस आधार पर घाटे में कितनी कमी हुई है, आंध्र प्रदेश के 22 कस्बों में 1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक, कर्नाटक के 22 कस्बों में 2 प्रतिशत से 13 प्रतिशत तक, गुजरात के 19 कस्बों में 1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक और मध्यप्रदेश के 16 कस्बों में 1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक घाटे में कमी ला सका है । इसके अलावा, मंत्रालय लाभ देने के लिए इस स्कीम के तहत अधिकाधिक कस्बों को मुख्य रूप से शामिल करने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत 30,000 से 15,000 जनसंख्या को शामिल करने के कस्बों के लिए मानदण्ड में संशोधन करने के बारे में विचार कर रहा है ।

अंत में बजट। बजट में विभिन्न प्रस्तावों में भी विद्युत क्षेत्र को सरकार के द्वारा सहायता प्रदान के बारे में अच्छे संकेत मिल रहे हैं । मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इसकी जानकारी है, लेकिन मैं अभी आपको इसकी सूची दे दूंगा । उद्यम पूंजी निधि में अब विद्युत क्षेत्र भी शामिल है । कर पर रोक रखते हुए बाह्य वाणिज्यिक ऋणों में 20 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक कमी की गई है । पिछले वर्ष की भांति विद्युत क्षेत्र के लिए हमें 5000 करोड़ आरईईसी को 3000 करोड़ कर मुक्त बाण्ड दिए गए थे । इस बार भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ पहले आवंटित कर दिए गए । सरकार ने ईसीबी के माध्यम से ऋण लेकर आंशिक वित्त की अनुमति दे दी है, तथा कारपोरेट विश्व बाजार में निवेश करने के लिए अर्हक सांस्थानिक निवेशकों को अनुमति दी गई है । जिन कस्बों को आर ए पी डी आर पी स्कीम के तहत शामिल नहीं किया गया है उन कस्बों के लिए सरकार राष्ट्रीय विद्युत कोष नामक एक अन्य राज-सहायता स्कीम लाई है, जिसमें जिस किसी कस्बे को आर ए पी डी आर पी के तहत शामिल नहीं किया जाता है, यदि घाटा कम करने की योजना उस कस्बे के लिए शुरू की जाती है, तो सरकार राज सहायता के रूप में रियायत देगी जो मेरे विचार से ऐसी

परियोजनाओं के लिए इस राष्ट्रीय विद्युत कोष के माध्यम से 3 प्रतिशत से 7 प्रतिशत है। अतः दूसरे शब्दों में जो कुछ भी मैं आप से कह रहा हूँ वह यह है कि जो विषय भारतीय विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आए थे, चाहे वे ईंधन अथवा डिस्काम हानियों अथवा डिस्काम को वित्तीय स्थिति अथवा कोयले की आपूर्ति संबंधी करार आदि से संबंधित थे, उन पर फिलहाल ध्यान केंद्रित है तथा उनका समाधान किया जा रहा है, जो विद्युत क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

अब हम तिमाही तथा वर्ष के परिणामों के बारे में विचार करते हैं। मुझे आपके साथ विचार विमर्श करते समय इस बात की खुशी है कि हमारी ऋण संपत्तियां, परेशानी की स्थिति में है। इस बात के बावजूद कि बहुत से पत्रकार और अन्य लोगों के द्वारा जो तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है और जिसके बारे में अधिकांश लोग यह कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र कठिनाई में है। चौथी तिमाही में हमारी ऋण संपत्तियां 99,571 करोड़ से बढ़कर 1,30,072 करोड़ हो गई है जो 31 प्रतिशत वृद्धि है। तदनुसार, हमारी आय 2623 करोड़ से बढ़कर 3684 करोड़ हो गई है जो 40 प्रतिशत वृद्धि है। इसके परिणामस्वरूप कर के बाद हमारा लाभ 608 करोड़ से बढ़कर 818 करोड़ हो गया है, जो 35 प्रतिशत वृद्धि है तथा यह फैलाव 23 आधार प्वाइंट तक भी बढ़ गया है। हमारी लगभग 1,84,000 करोड़ की बकाया स्वीकृतियां भी हैं जो इस बात का अच्छा संकेत है कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा वार्षिक वितरण 40,000 करोड़ से अधिक का है। अतः एक बार आपके पास लगभग 1,84,000 करोड़ का आर्डर बुक हो जाए तो यह इस बात का अच्छा संकेत है कि हम भविष्य में भी अपनी विकास दर को बनाए रखेंगे।

इस किस्म के तिमाही निष्पादन के परिणाम स्वरूप हमारे वार्षिक आंकड़े इस प्रकार प्रतीत होते हैं। उसकी ऋण संपत्तियां वास्तव में 99,571 करोड़ से बढ़कर 1,30,072 करोड़ हो गई है जो 31 प्रतिशत वृद्धि है। वर्ष की कुल आय में 28 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है और यह 10,161 करोड़ से बढ़कर 13,037 करोड़ हो गई है, निवल ब्याज आय 3,523 करोड़ से बढ़कर 4,395 करोड़ हो गई है और 25 प्रतिशत की वृद्धि है। कर के बाद लाभ 2620 करोड़ से बढ़कर 3032 करोड़ हो गया है और यह वृद्धि 16 प्रतिशत है। कर के बाद तुलनात्मक लाभ 2522 करोड़ से बढ़कर 3095 करोड़ हो गया है और यह वृद्धि 23 प्रतिशत है। यह लाभ कुछ असाधारण मदों को समायोजित करने के बाद हुआ है और यह सामान्य तौर पर हमारे कार्यों से संबंधित नहीं है। अतः हमारा वार्षिक निष्पादन इस प्रकार से दिखता है।

मेरे विचार से कुछ अन्य मुद्दों को उजागर करना महत्वपूर्ण है। वे हैं – आरबीआई ने केंद्र तथा राज्य क्षेत्र के लिए ऋण संकेंद्रण हेतु 31 मार्च, 2012 तक हमें छूट दी थी। उन्होंने इसे एक प्रावधान के साथ मार्च, 2013 तक बढ़ा दिया है हम जून तक उन्हें एक रोडमैप प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे द्वारा मार्च 2016 तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

पिछले वर्ष हमने 36318 करोड़ जुटाए थे और इसमें 5000 करोड़ के कर मुक्त बाण्ड शामिल थे। हमने 29 मार्च को आईटीपी परियोजनाओं में से एक परियोजना नामतः नागपट्टनम – कुड्डालूर को विद्युत ग्रिड कॉर्पोरेशन को हस्तांतरित कर दिया है। हमारी दो सहायक कंपनियां हैं – पीएफसी और सीएएस।

पीएफसी सीएस – प्रकाशन कारोबार के लिए तथा पीएफसी ग्रीन एनर्जी के लिए है । उन्होंने कार्य आरंभ कर दिया है। हम आगामी एक महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 250 मिलियन डालर का ऋण लेने की योजना बना रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सिंडीकेट ऋण होगा। कीमत इसकी कुछ प्रतिस्पर्द्धात्मक है हम ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में व्यवसाय की संभावना की खोज कर रहे हैं जैसे भारतीय कंपनियां बाहरी खानों को प्राप्त कर रही है और भारत में विद्युत परियोजनाओं की खपत के लिए तथा गैस स्टेशनों के लिए गैस की खपत हेतु उत्पादन कर रही है । हमने 1 अप्रैल 2012 से सभी व्यवसाय कार्यों वाली अपनी ईआरपी प्रणाली को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है ।

हमने पिछले वित्तीय वर्ष में कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं और सभी का उल्लेख न करते हुए केवल एक या दो का ही उल्लेख किया है। हमने माननीय प्रधानमंत्री से आठवीं बार एमओयू उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया है जो विद्युत मंत्रालय के साथ लक्ष्य निर्धारित करने की एक प्रणाली है । हमने अपनी भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया से बैंक, वित्तीय संस्थान / बीमा कंपनी की श्रेष्ठ प्रबंध व्यवस्था करने के लिए स्कोप प्रशंसनीय पुरस्कार के लिए गोल्ड ट्राफी एवं बहुत से और पुरस्कार प्राप्त किए हैं । हमने अगले वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए विद्युत मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं जिसके द्वारा स्वीकृति हेतु हमारे लक्ष्य 46234 करोड़ के हैं और वितरण लगभग 43000 करोड़ तथा संसाधनों की गतिशलता 40500 करोड़ है ।

तिमाही का हमारा औसत लाभ पिछले वर्ष के 10.81 प्रतिशत की तुलना में 11.32 प्रतिशत था और उसके परिणामस्वरूप वार्षिक लाभ 11.02 प्रतिशत की तुलना में 11.25 प्रतिशत हुआ । तिमाही की निधियों की लागत 8.71 प्रतिशत की तुलना में 8.99 प्रतिशत थी तथा निधियों की वार्षिक लागत 8.53 प्रतिशत की तुलना में 9 प्रतिशत थी और फैलाव के बारे में मैंने पहले ही बताया है यह तिमाही के लिए 2.10 प्रतिशत की तुलना में 2.33 प्रतिशत है और वर्ष के लिए यह 2.49 प्रतिशत की तुलना में 2.25 प्रतिशत है । ऐसे उच्च विकास के परिणामस्वरूप हमारा पूंजी पर्याप्तता अनुपात पिछले वर्ष 3400 करोड़ के अतिरिक्त हमारे एफपीओ के बावजूद लगभग 16.29 प्रतिशत रहता है । हमने जनवरी – फरवरी में अंतरिम लाभांश के रूप में 50 प्रतिशत का भुगतान किया है और अब अंतिम लाभांश के रूप में अन्य 10 प्रतिशत का भुगतान कर रहे हैं जिससे यह 60 प्रतिशत बनता है । एक अन्य विशेषता, जो सकारात्मक नहीं है, इसके बारे में यह कहूंगा कि हमारी गैर निष्पादन परिसंपत्तियां 0.23 प्रतिशत से बढ़कर 1.04 प्रतिशत हो गई है । इसका मुख्य कारण दो परियोजनाओं को जुड़वाना था । एक के बारे में हमने तीसरी तिमाही में पहले ही घोषणा कर दी थी । कोणासीमा गैस परियोजना चालू है परंतु गैस पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं है । इसलिए यह सेवा नहीं दे सकी है । एक अन्य परियोजना पुरानी थी, जो कुछ समय से निर्माणाधीन है, लेकिन आरबीआई ने मार्च 2012 तक मानक परिसंपत्ति के रूप में उस ऋण के बारे में कार्यवाही करने हेतु हमें विशेष छूट दी थी जो मार्च में समाप्त हो गई थी और इसलिए हमने इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया था अर्थात् मध्यप्रदेश में श्री महेश्वर जन विद्युत परियोजना के रूप में । इसके अलावा, 34 करोड़ रुपये के थोड़े ऋण वाली एम्पी पावर जिसके लिए हमने विवेकी मानदण्डों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अपेक्षित प्रावधान किए हैं हमारा निवल एनपीए अभी भी

0.93 प्रतिशत है इसी के बारे में आपके साथ विचार विमर्श करूंगा। यदि आपने कोई प्रश्न पूछना हो तो हमें उन प्रश्नों का उत्तर देने में खुशी होगी।

प्रश्न और उत्तर सत्र

वक्ता 1 : टीपीए बढ़ाया गया है, क्या डूबे हुए ऋणों की वसूली होने की संभावना है?

सतनाम सिंह : उदाहरण के लिए कोनासीमा गैस को लें; यदि सरकार संयंत्र के लिए गैस उपलब्ध कराने का निर्णय लेती है तो उस दृष्टि से यह एनपीए नहीं है क्योंकि वे अपेक्षित गैस की केवल दो तिहाई मात्रा में गैस प्राप्त कर रहे हैं, वे सर्विस देने की स्थिति में नहीं हैं। इसी प्रकार श्री महेश्वर जल विद्युत परियोजना चालू होने के लिए तैयार है, इसके लिए निधियों तथा पर्यावरण संबंधी स्वीकृति की जरूरत है, जो अब प्रदान कर दी गई है। इसे शीघ्र ही चालू किया जाएगा। अतः परियोजना के एक बार चालू कर दिए जाने पर यह तब उस स्थिति में एनपीए नहीं रहती है।

इसी प्रकार एक अन्य पवन (विण्ड) आधारित परियोजना आरएस इण्डिया जिसकी हमने पिछले वर्ष पुनः संरचना की थी, यह एक वर्ष तक पुस्तकों में एनपीए के रूप में रहेगी लेकिन उसके बाद यह एनपीए की श्रेणी से बाहर आ जाएगी। अतः इन सभी के बारे में मैं आप के साथ जो विचार विमर्श कर सकता था वह यह है कि एक अल्प समय अवधि में मानक परिसंपत्ति बन सकती है। लेकिन जब से हमने संरचना को अपनाया है उसी क्षण से यह एनपीए है।

वक्ता 2 : क्या अपने किसी निवेश में इक्विटी में ऋण को बदला है?

सतनाम सिंह : जी नहीं।

वक्ता 2 : पीएफसी का विद्युत क्षेत्र में आज की तारीख तक बाजार शेयर कितने हैं?

सतनाम सिंह : कुल बाजार शेयर के लगभग 20 प्रतिशत शेयर हमारे पास हैं।

वक्ता 2 : क्या इसमें बढ़ोत्तरी होने का अनुमान है?

सतनाम सिंह : इस बारे में ऐसा कोई अनुमान नहीं है परंतु हमारा प्रयास कम से कम 20 प्रतिशत के उस शेयर स्तर को बनाए रखने का है क्योंकि बाजार स्तर में बढ़ोत्तरी हो रही है।

वक्ता 3 : क्या डिस्काम की कमजोर वित्तीय स्थिति एक बहुत बड़ी चिंता है और क्या यह वास्तव में एक चेतावनी है?

सतनाम सिंह : ऐसा कुछ नहीं है। हम पिछले 25 वर्षों से राज्य विद्युत उपयोगिताओं को ऋण दे रहे हैं और मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने अब तक राज्य विद्युत उपयोगिताओं की ओर कोई ऋण बढ़े खाते नहीं डाला है तथा हमारा कोई ऋण डूबा नहीं है। एक ऋण था जो डूबा हुआ ऋण बन गया था

जो बिहार जल विद्युत परियोजना था, लेकिन पिछले वर्ष हमने उसकी भी वसूली कर ली थी । अतः जहां तक राज्य विद्युत यूटिलिटीज का संबंध है अब तक कोई भी डूबा हुआ ऋण बढ़े खाते नहीं डाला गया है । फिर भी घाटा करने वाले संघटन चिंता का विषय है। लेकिन सरकार द्वारा बाद में उठाए गए कई कदमों के फलस्वरूप इन विद्युत यूटिलिटीज की स्थिति पर अवश्य ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है । उदाहरण के लिए, मैंने कहा था कि केवल 14 राज्यों द्वारा ही टैरिफ संशोधन अथवा टैरिफ याचिका दायर की गई थी । वर्ष 2012-2013 के लिए 23 राज्यों ने टैरिफ याचिका और तदनुसार टैरिफ संशोधन दायर किए हैं। आपने सुना होगा कि तमिलनाडु ने 37 प्रतिशत टैरिफ बढ़ोत्तरी की है। यह बात पिछले 8-9 वर्षों से सुनी नहीं गई थी। लेकिन उन्होंने यह कर दिया । इसी प्रकार भारतीय विद्युत क्षेत्र के इतिहास में अगली बार एपीडीआरपी स्कीम की पुनः संरचना बेसलाइन डाटा वास्तव में स्थापित करने के लिए की गई थी । तथा घाटे में कमी लाने के लिए हम अत्याधुनिक आईटी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं । एक विशेष क्षेत्र अथवा कस्बे में घाटे को कम करने का यही एक उचित स्तर है, जहां से उसमें और अधिक कमी लाने की जरूरत है ।

वक्ता 4 : क्या आप डिस्काम्स के लिए किसी ऋण को पुनः व्यवस्थित कर रहे हैं?

सतनाम सिंह : डिस्काम्स के लिए हमारी उधारी बहुत कम है यह केवल 3 से 4 प्रतिशत थी और हमने किसी भी ऋण को पुनः व्यवस्थित नहीं किया ।

वक्ता 4 : कोई भावी योजनाएं ?

सतनाम सिंह : नहीं ।

वक्ता 5 : जी, हां । बैंकों की एनपीए में बढ़ोत्तरी हो रही है । मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ पावर फाइनेंस के लिए नहीं होगा । क्योंकि हम केवल यह पता लगा रहे हैं कि हर बार एनपीए में बैंकों के लिए कमी आने की बजाए क्यों बढ़ोत्तरी हो रही है?

सतनाम सिंह : हमारे मामले में, चूंकि हम परियोजना के लिए वित्तीय व्यवस्था करते हैं तथा हम यह आश्वासन देते हैं कि हम वितरित निधियों का अपने वितरण संरचना के माध्यम से किसी अन्य प्रयोजन के लिए विशेष तौर पर राज्य क्षेत्र के लिए विपथन नहीं करते हैं । हम कहते हैं कि आप विद्युत परियोजना के लिए अपेक्षित सामग्री प्राप्त करें, बिल पास करें, हमें बिल भेजे और हम सीधे ही आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करेंगे । इस प्रकार, इससे कोई भी व्यक्ति हमारी धनराशि को नहीं ले सकता है और किसी अन्य प्रयोजन के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकता है, सिवाए उस प्रयोजन के लिए जिस प्रयोजन हेतु हमने स्वीकृति दी है । इस किस्म की संरचना से हमें यह आश्वासन देने में मदद मिलती है कि जिन परियोजनाओं के लिए हमने उधार दिया है वे बनाई जाती हैं। अतः परियोजनाओं का निर्माण हो जाने पर व अंततोगत्वा ऋण को वापस करने के लिए राजस्व पैदा करते हैं। हम बैंकों के तरह एनपीए के बढ़ने की उम्मीद नहीं करते हैं, जहां पर वे परियोजना के लिए वित्त व्यवस्था करते हैं, लेकिन परियोजना के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के अलावा बहुत से अन्य कार्य करते हैं।

वक्ता 5 : पीएफसी के साथ कौन प्रतिस्पर्धा कर रहा है? इन विद्युत कंपनियों के लिए उधार देने वाले कौन – कौन हैं?

सतनाम सिंह : बैंकों, आरईसी, आईडीएफसी, आईएल एवं एफएस सहित बहुत से हैं ।

वक्ता 5 : मेरा विचार यह है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और लाभ कम हो रहे हैं? क्या यह सही विचार है?

सतनाम सिंह : मैं यह नहीं कहूंगा । जी हां, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है; उस बारे में कोई संदेह नहीं है । लेकिन हमारे बहुत से सकारात्मक पहलू हैं, जो हमें अन्य के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जैसे हमारे पास सर्वोत्तम संभव कोटि निर्धारण (रेटिंग) है जो हमें प्रतिस्पर्द्धी दरों पर ऋण लेने की अनुमति देती है । बैंको की तुलना में हमारी प्रशासनिक लागत लगभग 1/6 वां अथवा 1/7 वां भाग है। बैंक न होने के कारण सीआरआर, एसएलआर तथा प्राथमिकता क्षेत्र में उधार देने संबंधी बातें हम पर लागू नहीं होती है । हमारी समस्त धनराशि रियायती दरों की अपेक्षा समान्य ब्याज दरों नियोजित की जाती हैं । बैंक में मेरे विचार से लगभग 60 प्रतिशत अथवा इतनी राशि रियायती दरों पर नियोजित की जाती है । विद्युत परियोजना के लिए निधियों की आवश्यकता बहुत ही लंबी अवधि के लिए होती है, जिसको बहुत से बैंक उनकी परिसंपत्ति देयता के अनुकूल न होने के कारण उपलब्ध नहीं करा सकते हैं । हम बहुत ही लंबी अवधि के लिए उधार देते हैं । बड़े होने के कारण अधिक भार वहन कर सकते हैं अथवा ब्याज आधारित ऋणों की अस्थायी, स्थिर दर पर ऋण देने के लिए अपने आकार का प्रयोग करते हैं । निवल मूल्य आकार बड़े-बड़े 4-5 बैंको को छोड़कर अधिकांश बैंकों का अधिकांशतः तीन गुना है । चूंकि विद्युत परियोजनाओं को काफी अधिक मात्रा में धनराशि की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें हमारे जैसे संगठनों की जरूरत है । अतः ये बहुत से सकारात्मक पहलू हैं जो हमारे पास है और जो हमें अपने प्रतियोगियों की तुलना एक ऊंचा आधार प्रदान करते हैं । अतः हम किसी प्रतिस्पर्द्धा से नहीं डरते हैं। कठिन समय के बावजूद हमारी विकास दर, परिसंपत्तियों का जहां तक संबंध है, 31 प्रतिशत रही है, जैसा मैंने आपको बताया था । हमारे पास लगभग 1,84,000 करोड़ के आर्डर बुक हैं । मुझे ऐसे किसी अन्य बैंक अथवा संस्थान के बारे में जानकारी नहीं है, जिसके पास बकाया स्वीकृति बुक अथवा आर्डर बुक का ऐसा बड़ा आकार हो।

वक्ता 6 : नमस्कार । आपने इस वित्तीय वर्ष में लगभग 40,000 करोड़ की आवश्यकता के बारे में उल्लेख किया था । क्या आप यह सोचते हैं कि आपको इसके लिए इक्विटी जुटाने की जरूरत है?

सतनाम सिंह : जी हां । रिजर्व बैंक हमसे उम्मीद करता है कि हम 15 प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता को बनाए रखें । मार्च की स्थिति के अनुसार यह 16.29 प्रतिशत है । अपने विकास पर निर्भर करते हुए, जिसे हम इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त कर लेंगे, यदि अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता हुई, तो निश्चित तौर पर इसके लिए इक्विटी जुटाई जाएगी। लेकिन, हम एक अन्य इक्विटी इश्यू के लिए योजना नहीं बना रहे हैं । हम पहले दो स्तरीय पूंजी प्राप्त करेंगे । वास्तव में हमने आज बोर्ड में 2500 करोड़ के चिरस्थायी बॉण्डों के लिए अनुमोदन प्राप्त किया था । हमें अतिरिक्त पूंजी की जरूरत होगी, यद्यपि अब की भांति लाभ उपलब्ध है ।

वक्ता 6 : इस बारे में क्या आप डालर से वित्तीय व्यवस्था करने को अधिक उपयुक्त समझते हैं? क्या आप इस बारे में विचार कर रहे हैं? डालर से अधिक मात्रा में वित्तीय व्यवस्था करना?

सतनाम सिंह : यह ऐसा समय नहीं है अथवा किसी अन्य क्षण पर डालर से वित्तीय व्यवस्था करने पर विचार कर सकते हैं। जब कभी घरेलू बाजार से अथवा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हमें ऋण लेना होता है, तो हम सदैव घरेलू उधार लागत से विदेशी मुद्रा की उधार लागत को पूर्णरूप से तुलना करते हैं। और यदि यह देखते हैं कि यह आकर्षक है, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उधार लेने जाएंगे। अब तक की लंबी अवधि 5 वर्षों से अधिक की है, तो यह पूर्णतः नियंत्रित आधार पर प्रतिस्पर्द्धात्मक दरें नहीं दे रही है।

वक्ता 6: क्या आप यह सोचते हैं कि यूरोपियन बाजारों, ग्रीक का कोई प्रभाव पीएफसी, आरईसी को प्रभावित कर सकेगा?

सतनाम सिंह : नहीं, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है क्योंकि हमारा कारोबार मुख्य तौर पर भारत में ही है। सिवाए उस स्थिति को छोड़कर, जब हम कुछ हद तक विदेशी मुद्रा ऋण पर निर्भर करते हैं। यह सीधे तौर पर हमारे समग्र कारोबार को प्रभावित नहीं कर रहा है। लेकिन प्रभावित करता है। यदि यह समग्र देश के स्तर को प्रभावित करता है तो देश स्तरीय विद्युत की आवश्यकता ऊपर अथवा नीचे होती है, परंतु सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करती है।

वक्ता 6: बैंक पूरे देश भर की विद्युत परियोजनाओं के लिए भारी मात्रा में वित्तीय व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए यदि ग्रीक अथवा यूरोप में कुछ होता है तो यह बैंकों को प्रभावित कर सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से आपकी कंपनी को प्रभावित कर सकता है?

सतनाम सिंह : नहीं, वस्तुतः प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि भारतीय विद्युत क्षेत्र का जहां तक संबंध है, मांग की तुलना में काफी अंतर होता है। क्षमता में बढ़ोत्तरी सटीक नहीं होती है। अतः यदि कोई प्रभाव होता भी है तो इससे विद्युत क्षेत्र के प्रभावित होने की संभावना नहीं होती है। मैं आपको सूचित करता हूं कि वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान, यद्यपि यह एक पुराना आंकड़ा है, वित्तीय संकट से पूर्व हमारी विकास दर 15 प्रतिशत थी। वित्तीय संकट के बाद हमने विकास दर 30 प्रतिशत तक दुगुनी कर दी। इसलिए, क्या यह वास्तव में वित्तीय संकट था अथवा एक वरदान था, इसकी हम जांच करना चाहते हैं।

वक्ता 6: विदेशी संस्थान निवेशक एक संभावित निवेश अवसर के रूप में पीएफसी को किस प्रकार से देख रहे हैं?

सतनाम सिंह : लगभग 27 प्रतिशत सरकारी हैं और इनमें विदेशी वित्तीय संस्थान शामिल है तथा वे भारतीय विद्युत क्षेत्र में निवेश करने में बहुत अधिक उत्सुक हैं।

वक्ता 6: आपका एनपीए पिछले एक वर्ष में बढ़ गया है। क्या आप यह सोचते हैं कि अगले 12 महीनों में तुलन पत्र पर परिसंपत्तियों का कोई दबाव होगा?

सतनाम सिंह : जी नहीं । क्योंकि सबसे बड़ी परियोजना जो एनपीए में चली गई है, श्री महेश्वर (700 करोड़) है। यह सुप्रसिद्ध थी क्योंकि रिजर्व बैंक ने मार्च, 2012 तक हमें विशेष राहत दी थी । अतः यह आश्चर्यजनक बात नहीं है । चूंकि गैस पूरी मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण कोनासीमा गैस भी आश्चर्यजनक नहीं है। जहां तक हमारे एनपीए का संबंध है, किसी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं हुआ है । जैसे ही परियोजना पूरी कर ली जाती है अथवा गैस उपलब्ध करायी जाती है ये कुछ ही समय में मानक परिसंपत्तियां बन जाएंगी।

वक्ता 6: मैं यही प्रश्न दुबारा पूछ रहा हूं। चूंकि ये आश्चर्यजनक घटनाएं नहीं थीं तो क्या आप यह महसूस करते हैं कि ये आश्चर्यजनक हो सकती है?

सतनाम सिंह : एनपीए में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी करने की और उम्मीद नहीं है ।

वक्ता 6 : यूएमपीपी की प्रगति की क्या स्थिति है?

सतनाम सिंह : मैंने उस बारे में बताया था, लेकिन इसे सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए 15 में से 4 के बारे में पहले ही निर्णय ले लिया गया है । ओडिसा और छत्तीसगढ़ की दो परियोजनाओं के लिए कुछ संशोधनों सहित पुराने दस्तावेजों पर ही बोली लगाने की अनुमति दी गई थी । ओडिसा के लिए हमने आरएफक्यू प्रक्रिया पूरी कर ली है और इसका मूल्यांकन किया जा रहा है । जैसे ही आरएफपी के लिए नए दस्तावेज उपलब्ध हो जाते हैं, हम आरएफक्यू के लिए सफल बोलीदाताओं की घोषणा करने के साथ आगे बढ़ेंगे । छत्तीसगढ़ में हमारे पास आरएफक्यू हैं लेकिन निषेध क्षेत्र होने के कारण हमें इसको कई बार स्थगित करना पड़ा है और अभी हाल में हमने दुबारा इसे आस्थगित किया है । अगली यूएमपीपी तमिलनाडु में चेयूर यूएमपीपी है जो आरएफक्यू के लिए तैयार है । आरएफक्यू जारी करने के लिए हमने सभी पूर्व अपेक्षाओं को पूरा किया है, लेकिन उसके लिए भी नए दस्तावेज जारी करने हेतु मंत्रालय की प्रतीक्षा कर रहे हैं । शेष परियोजनाओं के बारे में या तो स्थलों को अंतिम रूप देने के लिए या फिर और अध्ययन करने के लिए राज्य सरकारों के साथ विचार –विमर्श किया जा रहा है।

वक्ता 7 : भारत में बार-बार यह देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में फीड स्टॉक के मूल्यनिर्धारण में अत्यधिक अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में अत्यधिक कमी आयी है, चाहे यह कोयले के बारे में अथवा प्रकृतिक गैस अथवा किसी अन्य चीज के बारे में हो । यदि सरकार पर पहले ही अत्यधिक दबाव है, हमारे पास यह कोर्ट का मामला है, जो कोल इण्डिया आदि में चल रहा है । यदि इसमें से कुछ उजागर होता है तथा फीड स्टॉक ऊपर उठता है, चाहे यह गैस अथवा कोयला हो, मैं उपलब्धता की बात नहीं कर रहा हूं, केवल मूल्य निर्धारण की बात कर रहा हूं, तो इस क्षेत्र के दबाव को कम करने के लिए पीएफसी की क्या रणनीतियां हैं? और यदि दरें उस दर से अधिक होनी थी, यदि आप पिछले 10 वर्षों को देखते हैं, तो बिजली की दरों सीएजीआर आधार पर ऊंची हो गई हैं, जो फीड स्टॉक दरों से बहुत कम है, तो इस जोखिम को कम करने के लिए पीएफसी की क्या रणनीतियां हैं?

सतनाम सिंह : पीएफसी को उस स्थिति के बारे में कार्रवाई करने के लिए कोई रणनीति बनानी होती है क्योंकि यदि उत्पादों के मूल्य निर्धारण में कोई परिवर्तन होता है तो यह हरेक के लिए होगा । यदि एक अथवा दो अथवा चार कंपनियों के लिए इक्का दुक्का मामले में किया जाता है तो रणनीति बनायी जाती है । लेकिन यदि हम कहें कि सभी विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले की कीमतें ऊपर अथवा नीचे होती हैं, तो इससे क्या अंतर पड़ेगा । इससे बिल्कुल अंतर नहीं पड़ेगा ।

वक्ता 7 : लेकिन, क्या आपका मानना है कि विद्युत की उच्चतर सांकेतिक कीमतों पर मांग वश में रहेगी?

सतनाम सिंह : हमारा अनुभव यह दर्शाता है कि लोगों ने 14 रु से अधिक मूल्य पर विद्युत खरीदी है । राष्ट्रीय औसत टैरिफ केवल 3 रु. से थोड़ा कम है । इसलिए, यदि कीमतें ऊपर जाती है तो भी पर्याप्त मांग की काफी गुंजाइश है । मैं नहीं समझता हूँ कि इसका प्रभाव पड़ेगा। फिर भी जब लोग यह समझेंगे कि यह ढांचागत परिवर्तन के कारण हुआ है, वह तब यदि भारत सरकार ऐसा करने के लिए एक दम निर्णय लेती है ।

वक्ता 7 : लेकिन आप कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि अगले 10 वर्षों में कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होने का रूझान विद्युत की कीमत की तुलना में उल्टा होना चाहिए।

सतनाम सिंह : जहां पर अगले 10 अथवा 12 वर्षों में सतत आधार पर मूल्य में बढ़ोत्तरी हो सकती है, वहां पर कोई उत्पादन नहीं हो सकता है । तब उत्पाद की कीमत उस स्तर पर पहुंच जाएगी जहां पर लोग विकल्पों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे । भारतीय विद्युत क्षेत्र में पहले से ही अथवा उस मामले में पूरे विश्व में सौर विद्युत तथा वायु आधारित प्रोडक्शन अथवा उत्पादन के बारे में सोच रहे हैं । यदि अधिक संख्या में परियोजनाएं सौर अथवा वायु के आधार पर सामने आती है, तो यह संभावना है कि कोयला कंपनियों को कीमत कम करनी पड़ सकती है । निकट भविष्य में नही अपितु 5 से 7 वर्षों में कीमत में कमी आ सकती है ।

वक्ता 8 : आपकी ऋण पुस्तिका पर रूपए के अवमूल्यन के क्या प्रभाव पड़ते हैं?

सतनाम सिंह : कुल ऋण की तुलना में हमारा विदेशी मुद्रा ऋण न्यूनतम है। यह लगभग 5 प्रतिशत अथवा इतना ही कम है । अतः इसके अलावा हमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रूपए में विदेशी मुद्रा ऋण लेने की अनुमति दी है, रूपए के ऋण, जिसमें यदि हमारी विदेशी मुद्रा में ऋण लागत 4 प्रतिशत अथवा 5 प्रतिशत हो, तो 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत के बीच ऋण उधार ले रहे हैं, जिसका अर्थ यह है कि इसमें स्वतः ही कुछ किस्म की कवरेज हो जाती है । लेकिन हमारे पास विभिन्न बेंचमार्कों पर निर्भर करते हुए विदेशी मुद्रा के बचाव की नीति है । यदि वे उस बेंचमार्क को पार करते हैं प्रत्येक विदेशी मुद्रा एक विशेष बेंचमार्क को पार करती है तब एक समिति होती है जो उस विदेशी मुद्रा के बचाव की देखरेख करती है। इस प्रकार, हम उस दृष्टिकोण से बच जाते हैं। यह हमें प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि प्रतिशतता न्यूनतम होती है। यह हमें उतना प्रभावित नहीं करती है । इसके अलावा, सरकार ने यह अनुमति दी है कि प्रत्येक मुद्रा ऋण की क्षतिपूर्ति होने तक आप इसे चुका सकते हैं । इसलिए हमने उसके लिए विकल्प दिया है और इसलिए इसने हमें इतना प्रभावित नहीं किया है।

वक्ता 9 : क्या एक समय अवधि के भीतर पीएसयू के बहुत अधिक आश्रित एवं कुशल बनने की गुंजाइश है? क्योंकि हमारा विचार यह है कि विगत में हम थोड़े सुस्त रहे हैं और अब दबाव पड़ने पर प्रकट हो रहे हैं; वे अधिक कुशल बन रहे हैं । उसी वजह से, दक्षता में सुधार लाने की काफी गुंजाइश होनी चाहिए तथा अधिक आश्रित बनते हैं तथा उसके द्वारा आपकी लाभ की स्थिति में थोड़ा-सा सुधार आना चाहिए ।

सतनाम सिंह : मुझे इस बात की खुशी है कि आपने यह मुद्दा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उठाया है। अब मैं आपको हमारी कंपनी के बारे में कुछ आंकड़े देना चाहूंगा, जिसके बाद मैं यह आप पर छोड़ता हूँ कि आप यह अनुमान लगाए कि क्या हम दक्ष हैं अथवा दक्ष नहीं हैं । हमें देश में प्रति कर्मचारी कर के बाद उच्चतम लाभ प्राप्त करने के लिए एक पुरस्कार प्राप्त हुआ था । यह औसतन प्रति कर्मचारी कर के बाद लाभ 8 करोड़ है । अब मैं इसे आपकी समझ पर छोड़ता हूँ कि क्या इसे रखना अथवा न रखना किसी कंपनी के लिए यथेष्ट रूप से ठीक है । हमारे पास 1,30,000 करोड़ की एक परिसंपत्ति पुस्तिका है और हमारे यहां लगभग 340 व्यक्ति हैं जिनमें से 230-240 एकजीव्युटिव हैं और अन्य सहायक कर्मचारी हैं ।

वक्ता 9 : पीएफसी सदैव ही अधिक कुशल रही है, जिसके बारे में सभी जानते हैं । हम केवल यह पता लगा रहे हैं कि क्या बहुत ज्यादा दक्षता प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक गुंजाइश है। यही ऐसा विचार है जिसके बारे में हम सोचते हैं ।

सतनाम सिंह : यहां पर हम अत्यधिक जन शक्ति को बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। जनशक्ति के बजाए हम प्रौद्योगिकी पर अधिक भरोसा कर रहे हैं । अतः जो कुछ भी हमने विगत में किया था, उसी स्तर को हम बनाए रखेंगे ।

वक्ता 10: ब्रोकर समुदाय के बारे में मेरे पास बहुत से प्रश्न हैं। एक प्रश्न यह है कि पिछले वर्ष हमने कुछ उत्पादों का उत्पादन हुआ है जिनको हमने खरीदा है, सर्वप्रथम शेयरों का एफपीओ इसके बाद इन्फ्रा बाण्ड और फिर कर मुक्त बाण्ड । जिन व्यक्तियों ने एफपीओ में निवेश किया है, उनकी राशि समाप्त हो गयी है। तुलन पत्र के बारे में ऐसा कुछ नहीं है जिस पर प्रश्न किया जा सके । 25 के ईपीएस को 6 पीई में बदलना आदि के बारे में प्रश्न नहीं किया जा सकता । यह पीएफसी की अंतर्भूत कीमत को नहीं दर्शाता है जो इसकी है। मैं आश्वस्त नहीं हूँ, लेकिन मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोग उसका समाधान करने के लिए कुछ कर सकते हैं, ताकि निवेशकों में कुछ हद तक विश्वास पुनः बनाया रखा जा सके । दूसरा भाग वितरक समुदाय के संबंध में है । जो उत्पाद हम पीएफसी के लिए खरीदते हैं उनके बारे में मैंने देखा है कि पीएफसी द्वारा दिया गया रूपया बहुत कम है । यह राशि वितरण व्यय को शामिल करने के लिए भी वास्तव में अपर्याप्त है आपको इसका समाधान करने की जरूरत है क्योंकि हम तो बाजार में ब्राण्ड पीएफसी को वस्तुतः बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार तुलन पत्र तथा आपके द्वारा दिए गए आंकड़ों को देखने पर आप को यह विश्वास हो सकता है मैंने पटल पर कुछ बेहतर आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।

सतनाम सिंह : मेरा विचार है यदि हम आपके सुझावों में से किसी भी सुझाव का पालन करते हैं तो आपके एक प्रश्न का उत्तर देने से रह जाएगा यदि मैं संसाधन जुटाने के लिए अधिक भुगतान करता हूँ, तो मेरी ऋण

लागत बढ़ जाएगी और इसलिए मेरा लाभ कम हो जाएगा। आप एक निवेशक के रूप में यह पूछने जा रहे हैं कि मैं क्या करता। आपके लाभ की स्थिति में कमी आई है, लेकिन यदि मैं इस दिशा में कुछ करता हूँ और उस लाभ को बनाए रखता हूँ तो ऋण का, जहां तक संबंध है, मुझे अनिवार्यता है कम भुगतान करना होगा। अतः मेरे विचार से यह एक परस्पर सहमति का मामला है। आप यह देखते हैं कि यदि बाजार हमें अनुमति नहीं देता है तो हम उस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बाजार समुदाय हमें संसाधन जुटाने के लिए सबसे कम लागत देने की हमें अनुमति दे रहा है और हम वह कार्य कर रहे हैं। अतः मुझे विश्वास है कि उसने दक्षता संबंधी मुद्दे को उठाया था, इसे करने का यह एक कुशल तरीका है। जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है प्रतिशेयर आय बाजार मूल्य में दिखाई नहीं जाती है। वास्तव में मुझे ब्रोकर और निवेशक समुदाय से वह प्रश्न पूछना चाहिए कि जब किसी कंपनी के डाटा उपलब्ध है, तो ऐसा क्यों है कि शेयर मूल्य में बढ़ोत्तरी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि डाटा कंपनी के निष्पादन के बारे में बताते हैं। आपको हमें यह बताना होगा कि जब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के आंकड़े आपके पास उपलब्ध है जो यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि मूल्य वह नहीं है जो होना चाहिए। लोगों को निवेश करना चाहिए तथा खरीद करनी चाहिए।

वक्ता 11 : सरकार का पीएसयू में हस्तक्षेप, उच्चतर मूल्य निर्धारित के लिए उनका जनादेश, चाहे यह विद्युत ग्रिड के लिए हो, अथवा एनबीसीसी के लिए हो, यह फिलहाल कठिनाई पैदा कर रही है। आपकी बातचीत को इससे काफी ऊपर बताया जाएगा, क्या आपकी एफपीओ कीमत कम रही थी?

सतनाम सिंह : पश्च दृष्टि से आप ऐसा कह सकते हैं, परंतु जब हमने 85 पर आईपीओ जारी किया था और कीमत 385 तक पहुंच गई थी। आप यह नहीं कह सकते थे, अथवा उस मामले के बारे में किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की थी। लेकिन, जब एफपीओ व्यक्तियों के लिए 203 अथवा 193 पहुंच गया था, तब यह मुद्दा बन गया क्योंकि इसमें अस्थायी तौर पर कमी आयी थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कंपनी की विश्वसनीयता के बारे में कंपनी ने उस समय पर कहा था, क्या वह उससे भिन्न पायी गई है। एफपीओ में जब मैंने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा था कि यह वह जो हम करेंगे, क्या मैंने यह किया है अथवा नहीं किया है? इसी के बारे में आपके मन में विश्वास बैठाना है; इसके अन्य कारण हैं जो कंपनी के निष्पादन से भिन्न हैं ये कारण मूल्य को प्रभावित कर रहे हैं और न कि कंपनी के निष्पादन को प्रभावित कर रहे हैं।

वक्ता 11 : जी नहीं। एफपीओ कीमत सहनीय नहीं दिखती थी और ऐसी उम्मीद नहीं थी। कीमत नीचे आयी। यह भावनाओं को प्रभावित करती है। हो सकता है कि आपकी अंतर्निहित कीमत ज्यादा हो। लेकिन यदि यह होता है तो निवेशक भाग जाते हैं छोटी सी बात सरकार नहीं समझती है अपितु आपको एफपीओ की उपेक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि आप एफपीओ के समर्थन में आगे आए तो कम से कम आप को यह सोचना चाहिए कि कीमत कम नहीं होनी चाहिए अन्यथा निवेशक भाग जायेंगे। मैं उन में से एक था जिसने यह महसूस करते हुए एफपीओ के लिए आवेदन नहीं किया था कि कीमत कम होगी और फिर कीमत में उचित रूप से कमी आयी लेकिन जो इस मूल्य पर आज भी है।

सतनाम सिंह : आपकी सूचना के लिए केवल हमारी कंपनी का एफपीओ ही था जो कठिन परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक अधि अतिदत्त था। अर्थात् निवेशकों का प्रतिबिंब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के विश्वास को बनाए रख रहा है और उसके लिए हम आभारी हैं।

वक्ता 11 : कंपनी अच्छी है, कंपनी कुशल है यह दूसरों की तुलना में विश्वास को प्रोत्साहित करती है। इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु सामान्य तौर पर हम यह महसूस करते हैं कि कीमत को ऊंचा रखना सरकार की इच्छा होती है।

सतनाम सिंह : ठीक है। कोई और बात है?

वक्ता 12 : वर्तमान वित्तीय वर्ष में कर मुक्त बाण्ड के रूप में आम जनता के लिए निधियां जुटाने की कोई योजनाएं हैं?

सतनाम सिंह : जी हां, जैसा कि मैंने पहले कहा था भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए बजट में सरकार द्वारा 10,000 करोड़ के कर मुक्त बाण्ड आवंटित किए गए हैं। हमें कितने दिए जायेंगे, यह उस समय देखा जाएगा जब अधिसूचना जारी होगी। लेकिन हां, कर मुक्त बाण्ड, निश्चित रूप से।

वक्ता 13 : यह कर मुक्त बाण्ड एक या दो दिनों में अधि अतिदत्त होते हैं, इसका मतलब है कि इसका हमारे जैसे छोटे लोगों के लिए कोई महत्व नहीं है जो एक या दो लाख लगाना चाहते हैं।

सतनाम सिंह : पहले दिन निवेश करने से आप को कोई नहीं रोकता है। यह मांग और आपूर्ति का एक प्रश्न है। मैं एक उत्पाद के साथ आता हूं और बहुत पहले यह घोषणा करता हूं कि मैं ऐसी ब्याज दर पर ऐसे उत्पाद के साथ आ रहा हूं, यह उत्तर देने वाले पर निर्भर करता है कि वह एक दिन, दो दिन, तीन दिन, और जब भी वह यह उपयुक्त समझे तब उस अवसर का अभिग्रहण कर सकते हैं।

वक्ता 13 : लेकिन खुदरा निवेशकों के लिए कुछ रखना चाहिए।

सतनाम सिंह : हम रखते थे। खुदरा निवेशकों के लिए कर मुक्त बाण्ड का हमारा पिछले वर्ष का पब्लिक इश्यू चौदह दिनों के लिए खुला रहा न कि एक दिन के लिए। और हमने यह किया यह कहते हुए कि हम नहीं करेंगे। यद्यपि खुदरा श्रेणी के लिए अधि अतिदत्त को समायोजित करने तथा पुनः आवंटित करने का हमारे पास विकल्प था; हमने वह नहीं किया था। हम खुदरा निवेशकों को प्रोत्साहित करना चाहते थे और सीमा 1 लाख नहीं थी, यह 5 लाख है।

वक्ता 13 : यह अवसर कभी – कभी आता है।

सतनाम सिंह : चिंता न करें।

वक्ता 13 : सरकार खुदरा निवेशकों अपना धन रखने भी नहीं दे सकती है।

सतनाम सिंह : मैं आपसे सहमत हूँ ।

वक्ता 13 : बड़े – बड़े निवेशक हैं । उनके पास नकद राशि अधिक है और हर चीज रखते हैं ।

सतनाम सिंह : मैं आपको यह बताता हूँ कि इस वर्ष कर मुक्त बाण्ड 60,000 करोड़ के होने जा रहे हैं न कि 30,000 करोड़ के । इसलिए हरेक के लिए निवेश करने का पर्याप्त अवसर होगा ।

वक्ता 14 : पर्यावरण कठिन है, बड़ी – बड़ी परियोजनाएं हटाई नहीं जाती है, तब उनकी लाभकारी स्थिति सामने आती है, इसलिए यदि लाभकारी स्थिति सामने नहीं आती है, तो आप धनराशि का भुगतान कैसे करेंगे?

सतनाम सिंह : किसने कहा था कि पर्यावरण कठिन रहे अथवा लाभकारी स्थिति सामने नहीं आ रही है? यदि लाभकारी स्थिति सामने नहीं आ रही है, हम 25 वर्षों के लिए ऋण दे रहे हैं और उन 25 वर्षों में, एक रूपया भी डूबा हुआ ऋण नहीं बना है। लोग कहते हैं कि राज्य क्षेत्र के पास भी धन नहीं है और वे खतरे में हैं तथा वे कोई धन नहीं देते हैं, हम उनको भी ऋण दे रहे हैं। लेकिन हमने कभी एक पैसा भी बट्टे खाते नहीं डाला है। इसलिए यह नहीं है कि लाभकारी स्थिति नहीं है। लाभकारी स्थिति है; लेकिन कभी-कभार इक्का-दुक्का परियोजनाएं हो सकती है जो कार्यान्वित नहीं होती है ये सब कुछ खेल का एक हिस्सा है। सभी कुछ सदैव कुशल नहीं हो सकता है।

वक्ता 14 : आपका बहुत – बहुत धन्यवाद ।

वक्ता 15 : आपके अनुसार स्टॉक का उचित मूल्य क्या है?

सतनाम सिंह : मेरे विचार से ऐसा विवरण देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ । जिस मूल्य पर आप खरीदने के लिए तैयार होते हैं वही उचित मूल्य होता है। धन्यवाद । बहुत – बहुत धन्यवाद ।

संचालक : इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद । अब प्रबंधन की ओर से मैं आप सभी को हाई-टी के लिए आमंत्रित करता हूँ।

टिप्पणी : 1. पठनीयता में सुधार लाने के लिए इस दस्तावेज का सम्पादन किया गया है।

2. इस प्रतिलिपि में खाली स्थान अश्रव्य अथवा अबोध शब्दों को दर्शाते हैं।